



## छत्तीसगढ़ राज्य की नई उद्योग नीति का अध्ययन

डॉ. अनीता मेश्राम

आसिस्टेंट प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स, मोहन लाल जैन कॉलेज, खुर्सीपार, भिलाई, छत्तीसगढ़

### भूमिका

उद्योग विकास किसी भी देश की रीढ़ है या हम कह सकते हैं कि यदि किसी देश को विकास करना है तो उद्योगों का विकास अनिवार्य है भारत में नई उद्योग नीति की घोषणा 1956 में की गई तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबंध में की थी इस संबंध में पंडित नेहरू ने कहा था की योजना असंगठित समाजवादी ढांचे पर समाज की स्थापना को देश के सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य बनाया है।

### उद्योग नीति का अर्थ

उद्योग नीति का अभिप्राय उन व्यापक नीतिगत उपायों से है जिसका संबंध देश के विभिन्न प्रकारों के औद्योगिक उपक्रमों से होता है जिस देश में औद्योगिक विकास के स्वरूप प्रक्रियाएं सिद्धांत एवं उद्योगों के नियंत्रण के लिए नियम शामिल होते हैं।

### अध्ययन का उद्देश्य

यह ज्ञात करना कि औद्योगिक नीति के निर्माण से देश के आर्थिक विकास में कितनी वृद्धि हुई।

### परिकल्पना

- यह परिकल्पना निर्धारित किया गया है कि उद्योग नीति निर्माण के फल— स्वरूप देश का आर्थिक विकास हुआ है
- औद्योगिक नीति से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

### अध्ययन तकनीक

प्रस्तुत अध्ययन हेतु हमने द्वितीयक समंको को सम्मिलित किया है।

### नई उद्योग नीति

भारत में 1991 की नई उद्योग नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न है:

- 5 उद्योगों के अतिरिक्त सभी उद्योगों को लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त किया गया है 18 उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
- 9 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है जो हथियार, गोला बारूद प्रतिरक्षा संबंधी उपकरण आदि।
- उच्च प्राथमिक उद्योगों में विदेशी निवेशक की आकर्षित करने के लिए सरकार ने ऐसे उद्योग को 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का सरकार ने निश्चय किया है।
- देश में निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार विदेशी व्यापारिक कंपनी को प्रोत्साहित करेगी।
- पंजीकरण की समस्त योजनाओं को समाप्त किया गया है।

- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के अलावा अन्य नगरों में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

### नई औद्योगिक नीति बनाम छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, उस समय राज्य के हिस्से में कुछ ही इकाइयां थी, उसके पश्चात् छत्तीसगढ़ में तेजी से औद्योगिकरण की वजह से राज्यों में 200 बड़ी और कोई छोटे उद्योगों का विकास हुआ।

### छत्तीसगढ़ के मुख्य उद्योग में से शामिल हैं:

इस्पात, अल्युमिनियम, सीमेंट, ताप, विद्युत खनन आदि। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन विकास की अपार संभावनाओं के साथ हुआ। राज्य ने अपने आर्थिक शक्तियों जैसे अपार खनिज संपदा, 44 प्रतिशत वन क्षेत्र श्रम की उपलब्धता आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की बदौलत देश में निवेशकों के पसंदीदा वस्तुओं के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा है। राज्य में सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना के आधार पर औद्योगिक नीति लागू की गई है 2001 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019, 2019 से 2024 और अब राज्य सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य में नई औद्योगिक विकास नीति 2024–2030 की घोषणा की है।

### 2014 से 2019 की औद्योगिक विकास

क्र	श्रेणी	न्यूनतम स्थानी पूंजी निवेश	स्थानी रोजगार
1	स्टील	500 से 1000 करोड	1000
2	सीमेंट	500 से 1000 करोड	1000
3	विद्युत	500 से 1000 करोड	1000
4	एल्यूमिनियम	500 से 1000 करोड	1000
5	इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक उपभोक्ता	50 से 100 करोड	250
6	फार्मास्युटिकल उद्योग	15 से 20 करोड	100
7	आई.टी. सेक्टर	15 से 230 करोड	250
8	टैक्सटाइल्स	50 से 100 करोड	250
9	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा	30 से 60 करोड	50

### 2019 से 2024 की औद्योगिक नीति

इस नीति में औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के सभी विकासखण्डों को औद्योगिक विकास एवं पिछड़ेपन की दृष्टि से क्रमशः अ, ब, एवं स श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहली बार प्रदेश सरकार ने सेवा क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया है।

औद्योगिक नीति 2019–24 में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत विकासखण्डों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु तीन श्रेणी में ब्याज व अनुदान देने का प्रावधान किया है।

श्रेणी	प्रतिशत	अनुदान अधिकतम राशि	अधिकतम वर्ष
सामान्य	40.65:	40 लाख	8 वर्ष
प्राथमिक	50.70:	50 लाख	10 वर्ष
उच्चप्राथमिक	50.70:	55 लाख	11 वर्ष

### प्रदेश में उद्योगों की स्थानीय मजदूरों की प्राथमिकता

उद्योगों को 100 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों की भर्ती स्थानीय लोगों से करनी होगी कुशल श्रमिकों के लिए 70 प्रतिशत और प्रबंधकीय प्रशासकीय पदों में 40 प्रतिशत मानव संसाधन की भर्ती स्थानीय लोगों से करनी है। छत्तीसगढ़ में 2023–24 में औद्योगिक क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 5.02 प्रतिशत वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में 2023–24 में जीएसडीपी औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 53.50 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 31.19 प्रतिशत रहा है।

### 2024 से 2019 की औद्योगिक नीति

औद्योगिक विकास की नई गति देने के उद्देश्य में नई विकास नीति 2024–30 की घोषणा की गई है। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशल युक्त रोजगारों का सृजन करते हुए अगले 5 वर्षों में 5 लाख नहीं औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है।

### औद्योगिक नीति 2024.30 का उद्देश्य

- अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 इस औद्योगिक विकास नीति 2024–30 का उद्देश्य यह है कि सभी विकासखंडों, जिले एवं संभाग स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार की नीति का क्रियान्वयन किया जाना, कि सभी क्षेत्रों में व्यवसाय का सुनियोजित एवं दीर्घकालिक विकास हो सके।
- राज्य के सभी जन सामान्य एवं इच्छुक उद्यमियों को अनुकूल एवं सहयोगी प्रशासनिक वातावरण उपलब्ध कराना, जिससे राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो सके।
- राज्य के सभी विकासखण्डों को औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाना, जिन क्षेत्रों में अधिक संभावना होगी उसी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पहले की जाएगी।
- राज्य की आवश्यकता के अनुसार नवीन तकनीकी पर आधारित उद्यम विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
- ऐसे बीमार एवं बंद उद्योग जिनके द्वारा पूर्व में अनुदान नहीं

लिया गया है उन्हें जिर्णोधार के लिए विशेष अनुदान प्रदान करना।

क्रमांक	वर्ष	औद्योगिक विकास दर	निवेश	रोजगार
1	2009 – 2014	औद्योगिक विकास दर 6.7:		
2	2014 – 2019	औद्योगिक विकास दर 7.5:	25: अधिक निवेश	कुल रोजगार में 10: वृद्धि
3	2019 – 2024	औद्योगिक विकास दर 7.1:	19500 करोड	33 हजार लोगो को रोजगार

उपरोक्त तालिका का यदि हम विश्लेषण करें तो यह ज्ञात हो रहा है कि 2009 से 2024 को औद्योगिक विकास की दर 6.07 प्रतिशत थी जो कि 2019 से 2024 की औद्योगिक नीति विकास की दर 7.01 प्रतिशत हो चुकी है। अर्थात औद्योगिक नीति के फलस्वरूप औद्योगिक विकास की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है।

### निष्कर्ष

- निष्कर्ष के रूप में हमारे अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है कि हमने जो परिकल्पना निर्धारित किया था कि औद्योगिक नीति के निर्माण के फलस्वरूप औद्योगिक विकास की दर में छत्तीसगढ़ राज्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। जो कि परिकल्पना को सही सिद्ध कर रहा है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक नीति के निर्माण के फल स्वरूप रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। 2014–2019 के औद्योगिक नीति से रोजगार के अवसरों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है इसी प्रकार 2019–24 के औद्योगिक नीति में 33,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है।
- इसी प्रकार 2024 से 2030 की औद्योगिक नीति में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- औद्योगिक नीति में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक निवेश में भी वृद्धि हुई है।
- औद्योगिक नीति के फल स्वरूप एवं प्रक्रियाओं पर नियंत्रण के फलस्वरूप राज्यों के विकास को गति मिली है।

### सुझाव

- राज्य में स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध करना जिससे रोजगार में वृद्धि व पलायन में कमी होगी।
- नए उद्योगों में निवेश की प्रोत्साहन
- नियमों में शिथलीकरण एवं सहभागिता बढ़ावी जावें।
- राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी स्थापित करें।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की उचित उपयोग किया जाए।
- कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध हो जिससे उद्योग स्थापित हों।

## संदर्भ सूची

1. अर्थशास्त्र 1 सेमेस्टर डॉ. भूमिका शर्मा
2. भारतीय अर्थशासन डॉ. चतुर्भुज मामोरिया एवं जे.पी. मिश्रा
3. दैनिक समाचार पत्र